विभागों के बीच तालमेल हो तो मुंबई कम कर सकता है वायु प्रदूषण, सीईईडबल्यू और अर्बन एमिशन के अध्ययन में बात आई सामने

मुंबई, प्रेस रिलीज, 30 जून 2020

मुंबई में स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लागू करना कोई मुश्किल काम नहीं है. बस इसके लिए विभागों के बीच आपसी तालमेल को और बेहतर करना होगा. बजट हैं, योजनाएं हैं, इनको लागू करने के लिए कई एजेंसियां लगी हुई हैं. ये बात हाल ही में काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडबल्यू) और अर्बन एमिशन द्वारा एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है. देशभर में स्वच्छ वायू कार्यक्रम के तहत चल रहे कार्यक्रमों का विश्लेषण करने के बाद यह बात सामने आई है.

मुंबई के स्वच्छ वायु योजना में अंकित 58 एक्शन पोइंट्स को लागू करने के लिए 16 एजेंसियों को नियुक्त किया गया है. ऐसे में अगर एजेंसियों की जिम्मेवारी नहीं तय करने पर समय सीमा के अंदर कार्यक्रम का लक्ष्य पूरा करने में बाधा आ सकती है.

महाराष्ट्र में सभी शहरों में स्वच्छ वायु योजनाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) के पास स्वच्छ वायु कार्यक्रम से जुड़ी केवल 20% गतिविधियों को लागू करने की जिम्मेदारी है. जबकि 41% नगर निगमों और शहरी स्थानीय निकायों के दायरे में आता है. वहीं परिवहन विभाग के तहत 22% योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी है. विश्लेषण में यह भी कहा

गया है कि महाराष्ट्र के सभी शहरों की स्वच्छ
वायु कार्यक्रम में कार्यान्वयन के लिए कानूनी समर्थन का आभाव है

भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) ने महाराष्ट्र में 17 सहित देशभर के 102 शहरों को शामिल किया गया है. इसके तहत उन्हें दिशा-निर्देश दिया गया है कि वह जरूरी कार्यक्रमों, उपायों को लागू कर साल 2024 तक 20% से 30% तक पार्टीकुलेट प्रदूषण को कम करें.

सीईईडबल्यू -अर्बन एमिशंस विश्लेषण के अनुसार महाराष्ट्र के 17 निर्धारित शहरों में मुंबई समेत मात्र छह शहरों के स्वच्छ वायु योजनाओं में बजट का आकलन है. इसके अलावा, 70 प्रतिशत से अधिक योजनाओं में प्रदूषण के स्त्रोतों पर जानकारी की कमी है.

सीईईडबल्यू की सहयोगी तनुश्री गांगुली का कहना है कि "महामारी की वजह से सभी गैर-जरूरी गतिविधियों पर रोक के कारण महाराष्ट्र के शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई है. आकाश को इसी तरह साफ रखने के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉग टर्म योजना बनाने की जरूरत है. तभी इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है. राज्य और नगर निगम के बजट में भी वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जरूरी खर्च को निर्धारित करने की आवश्यकता है.

अर्बन एमीशंस के संस्थापक और इस अध्ययन के लेखकों में से एक, सरथ गुट्टिकुंडा ने कहा, “महाराष्ट्र में स्वच्छ हवा की मांग जोर-शोर से होने लगी है. इसको पूरा करने के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शहर के अधिकारियों को मिलकर वायु प्रदूषण पर नज़र

रखना चाहिए. साथ ही तय करना होगा कि जिन चीजों से प्रदूषण बढ़ रहे हैं, उसको कितने समय में और कितना नियंत्रित कर लेना है. समय सीमा निर्धारण के साथ, इसके लिए काम कर रही एजेंसियों के काम और जवाबदेही का निर्धारण कर देना चाहिए. साथ ही इनके कामों की निगरानी कैसे हो, इसके लिए सभी विभागों के प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाना चाहिए.

महाराष्ट्र में नॉन-अटेंमेंट शहरों की संख्या 18 है जो की भारत के सभी राज्यों में से सभसे अधिक है. इन 18 शहरों में से ठाणे को छोड़कर बाकि 17 शहरों की योजनाएं प्रकाशित की हैं. महाराष्ट्र में नॉन- अटेंमेंट शहरों की संख्या अधिक होने के बावजूद सभी शहरों की योजनाओ एक-दुसरे से अलग है.

सीईईडबल्यू की एक रिसर्च एनालिस्ट कुरिन्जी सेल्वराज ने कहा, “मुंबई की कार्य योजना उन कुछ योजनाओं में से है जिसमें ये पता है कि पॉल्यूशन का सोर्स क्या है. साथ ही उससे निपटने के लिए पैसे के सही इस्तेमाल के रूटमैप की जानकारी है. लेकिन इन योजनाओं में रिजनल लेवल पर कॉर्डिनेशन का उल्लेख नहीं किया गया है. जबकि अध्ययन बताते हैं कि मुंबई का एक तिहाई प्रदुषण सीमा के बहार स्थित इलाकों से आ रहा है.

उन्होंने यह भी कहा कि, मुंबई वह शहर है जिसे बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा घोषित स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए 4400 करोड़ में से सबसे अधिक धनराशि मिला है. हालांकि, मुंबई को केंद्र सरकार से मिले 488 करोड़ रुपए मुंबई के दो एक्शन पॉइंट गाड़ियों की

नियमित पॉल्यूशन जांच और सार्वजनिक
साइकिल सेवा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, के बजट के बराबर है.

स्टडी प्रोसेस

सीईईडबल्यू-अर्बन एमिशन ने स्वच्छ वायु कार्यक्रम की व्यापक समीक्षा की है. इसके लिए इस योजना से जुड़ी एक-एक पहलू का अध्ययन किया गया है. अध्ययन के तहत कानूनी ढांचे, पॉल्यूशन के स्त्रोत की जानकारी, इसपर काम कर रही संस्थाओं की जिम्मेदारी आदि का गहन आकलन किया है. गहन आकलन इसलिए भी है क्योंकि इन सब मुद्दों पर जानकारी जुटाने के लिए कुल देशभर में चल रहे स्वच्छ वायु कार्यक्रम संबंधी 102 योजनाओं का अध्ययन किया गया है. इसके तहत देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे योजनाओं का आकलन किया गया है.

सीईईडबल्यू के बारे में

काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईवी) एशिया के अग्रणी नॉट फॉर प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च संस्थानों में से एक है. काउंसिल संसाधनों के इस्तेमाल, उसका दुबारा इस्तेमाल कैसे हो जैसी चीजों पर भी काम करती है. इसके लिए डेटा, डेटा का विश्लेषण, उसके इस्तेमाल की योजना बनाने के एक्सपर्ट के तौर पर काम करती है. साथ ही निजी और सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर रिसर्च करती है. इसके रिसर्च की क्वालिटी को विश्व स्तर का माना जाता है. साल 2020 में 'ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट-2019' में नौ कैटेगरी में अपना स्थान बनाया है. परिषद को दुनिया के शीर्ष

जलवायु परिवर्तन थिंक टैंकों में भी लगातार
स्थान दिया गया है. लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें @CEEWIndia पर फॉलो करें.

अर्बन एमिशन के बारे में

अर्बन एमिशन एक स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान है जिसकी स्थापना वायु प्रदूषण से संबंधित सूचना, अनुसंधान और विश्लेषण के लिए की गई थी. यह देशभर में एयर क्वालिटी की भविष्यवाणी, उसका प्रचार-प्रसार, उससे संबंधिक स्टडी करती है, खासतौर पर दिल्ली में. यह संस्था वायु प्रदूषण संबंधी रिसर्च, सूचना आदि का प्रदर्शन भारत, अफ्रीका, एशिया के कई देशों में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए प्रदर्शित करती है. भारत में 50 और एशिया-अफ्रिका के देशों में 10 से अधिक प्रदर्शन कर चुकी है. अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए ट्विटर पर फॉलो करें- @urbanemissions

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें-

रिद्धिमा सेठी - riddhima.sethi@ceew.in ; 9902039054

मिहिर साह - mihir.shah@ceew.in